



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 1, 2007/आश्विन 9, 1929

No. 293]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 2007/ASVINA 9, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2007

सं. 54(आर ई-2007)/2004—2009

फां. सं. 01/94/180/पोलिटिकल फार्म- ईपीसीजी/एचबीपी/ए एम 08/पीसी 1.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1. पैराग्राफ 5.3.1 को निम्नानुसार धारा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:—

5.3.1 संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, परिशिष्ट 32क में आवेदक द्वारा स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर (सीईसी) से नेक्सेस प्रमाण-पत्र के आधार पर ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र जारी करेगा और इस ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र की एक प्रति सम्बंधित क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारी को भेजेगा।

2. सार्वजनिक सूचना सं. 22 दिनांक 17-7-2007 द्वारा संशोधित पैराग्राफ 5.3.2 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

5.3.2 प्राधिकार-पत्र धारक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र आयात करने के 6 महीने के भीतर प्रस्तुत करेगा जिसमें यह दर्शाया गया होगा कि पूंजीगत माल प्राधिकार-पत्र धारक या सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं)/विक्रेता (विक्रेताओं) की फैक्टरी परिसर में अधिष्ठापित कर दिया गया है। स्पेयर्स के आयात के मामले में, अधिष्ठापना प्रमाण-पत्र को आयात की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर प्राधिकार-पत्र धारक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

तथापि, केन्द्रीय-उत्पाद-शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत न किए गए यूनितों के मामले में प्राधिकार-पत्र धारक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें पूंजीगत माल को अधिष्ठापित करने की पुष्टि की गई हो।

3. "निर्यात दायित्व की पूर्ति" से संबंधित पैराग्राफ 5.8 को निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:

5.8 ईपीसीजी स्कीम के तहत प्राधिकार-पत्र धारक निर्यात दायित्व निम्नलिखित अनुपात में विनिर्दिष्ट अवधि में पूरा करेगा:

प्राधिकार-पत्र जारी होने की तारीख की अवधि	न्यूनतम निर्यात दायित्व जिसे पूरा किया जाना है
1 से 6 वर्ष का ब्लाक	50%
7 और 8 वर्ष का ब्लाक	50%

4. पैराग्राफ 5.8.1 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:—

5.8.1 ऐसे प्राधिकार-पत्र जिन पर बचाए गए शुल्क का मूल्य 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक है, के संबंध में निर्यात दायित्व निम्नलिखित अनुपात में 12 वर्षों की अवधि में पूरा किया जाएगा:—

प्राधिकार पत्र जारी होने की तारीख की अवधि	न्यूनतम निर्यात दायित्व जिसे पूरा किया जाना है
1 से 10 वर्ष का ब्लाक	50%
11 और 12 वर्ष का ब्लाक	50%

5. पैराग्राफ 5.8.2 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:—

5.8.2 तथापि, विशिष्ट ब्लाक वर्ष के निर्यात दायित्व को, पिछले ब्लाक वर्ष में किए गए अधिक निर्यात द्वारा समंजित बढ़ाया जा सकता है। प्राधिकार-पत्र धारक ब्लाक पूरा होने के तीन महीनों के भीतर निर्यात दायित्व को पूरा करने और डिजिटल हस्ताक्षरों का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन सुनिश्चित करके वार्षिक रूप से औसत निर्यात के बारे में क्षेत्रीय प्राधिकारी को सूचित करेगा।

6. पैराग्राफ 5.8.3 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:—

5.8.3 जहाँ विशिष्ट ब्लॉक वर्ष का निर्यात दायित्व, उपर्युक्त अनुपातों की शर्तों के अनुसार पूरा नहीं हुआ है, ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ विशिष्ट ब्लॉक वर्ष के लिए निर्धारित निर्यात दायित्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया गया हो, तो ऐसे प्राधिकार-पत्र धारक उक्त ब्लॉक वर्ष की समाप्ति से 3 महीनों के भीतर उस सामान, जिसमें कुल निर्यात दायित्व का अपूर्ण निर्यात दायित्व के भाग के रूप में समाप्त अनुपात शामिल है, पर देय सीमा शुल्क (राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित लागू व्याज सहित) के अनुपात के समकक्ष सीमाशुल्क का भुगतान करेगा।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 1st, October, 2007

No. 54 (RE-2007)/2004—2009

F. No. 01/94/180/Pol. Form.-EPCG/HBP/AM 08/PC-I.— In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009 the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in Handbook of Procedures (Vol.1):

1. Paragraph 5.3.1 stands replaced by the following clause:

5.3.1 RA concerned shall, on the basis of nexus certificate from an Independent Chartered Engineer (CEC) submitted by the applicant in Appendix 32A, issue EPCG authorisation and thereafter forward a copy of the EPCG authorisation to the concerned Jurisdictional Central Excise Authority.

2. Paragraph 5.3.2 amended *vide* PN-22 dated 17-7-2007 stands replaced by the following:

5.3.2 Authorisation holder shall produce to the concerned RA a certificate from the Jurisdictional Central Excise Authority, confirming installation of Capital goods at factory premises of authorization holder or his supporting manufacturer(s)/ vendor(s) within six months from the date of completion of import. In the case of import of spares, the installation certificate shall be submitted by the Authorisation holder within a period of three years from the date of import. However, in case of units not registered with Central Excise Authorities, the Authorisation holder shall produce to the concerned RA, a certificate from an

independent Chartered Engineer confirming the said installation of Capital goods/spares.

2. Paragraph 5.8 related to "Fulfillment of Export Obligation" stands amended as follows:

5.8 The Authorisation holder under the EPCG scheme shall fulfill the export obligation over the specified period in the following proportions:

Period from the date of issue of Authorisation	Minimum export obligation to be fulfilled
Block of 1st to 6th year	50%
Block of 7th and 8th year	50%

3. Paragraph 5.8.1 stands amended as follows:

5.8.1 In respect of Authorisations, on which the value of duty saved is Rs. 100 crore or more, the export obligation shall be fulfilled over a period of 12 years in the following proportion:—

Period from the date of issue of Authorisation	Minimum export obligation to be fulfilled
Block of 1st to 10th year	50%
Block of 11th and 12th year	50%

4. Paragraph 5.8.2 stands amended as follows:

5.8.2 However, the export obligation of a particular block of year may be set off by the excess exports made in the preceding block of year. The Authorisation holder would intimate the regional authority on the fulfillment of the export obligation as well as average exports within three months of completion of the block, by secured electronic filing using digital signatures.

5. Paragraph 5.8.3 stands amended as follows:

5.8.3 Where export obligation of any particular block of years is not fulfilled in terms of the above proportions, except in such cases where the export obligation prescribed for a particular block of year is extended by the competent authority, such authorisation holder shall, within 3 months from the expiry of the block of years, pay duties of customs (alongwith applicable interest as notified by DoR) of an amount equal to that proportion of the duty leviable on the goods which bears the same proportion as the unfulfilled portion of the export obligation bears to the total export obligation.

This issues in Public interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade
and ex-officio Addl. Secy.